(b) Prior to 1st August, 92 Food Corporation of India was handling retail distribution of foodgrains in West Bengal on behalf of the State Government. The State Government withdrew the aforesaid work from FCI with effect from 1-8-1992, resulting in reduction of workload of FCI in the Region. In view of this, District Offices in the Region have been reorganised and reduced from 25 to 16 on the basis of the recommendations of the Zonal Committee.

(c) No, Sir. FCI has not declared any worker surplus.

(d) Does not arise.

4458. [*Transferred to the 24th August, 1993*]

जबलपुर में भारतीय खाद्य निगम का नवनिर्मित भवन

4459. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर में भारतीय अनाज संचयन संस्थान के नवनिर्मित भवन में गम्भीर त्रुटियां पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो भवन के निर्माता ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस भवन को अनाज संचयन संस्थान द्वारा इसमें अपना कार्यकरण आरंभ किए जाने हेतु सुरक्षित घोषित कर दिया गया है ; और

(घ) अनाज संचयन संस्थान ने इस भवन में कब से कार्य करना प्रारंभ किया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। खाद्य मंत्रालय के जबलपुर में स्थित एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय अनाज संचयन संस्थान के नवनिर्मित कार्यालय भवन में कुछेक त्रुटियां पाई गई। इस भवन का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है।

(ख) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंधित ठेकेदार को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों की सूची से खारिज कर देने का प्रस्ताव है और इस संबंध में इस ठेकेदार को जुलाई, 1993 में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का सतर्कता यूनिट भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उन विभागीय अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहा है जिन्होंने इस निर्माण कार्य की देख-रेख की थी।

(ग) और (घ) इस भवन के भूतल का अप्रैल, 1992 से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस भवन का पहला और दूसरा तल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रेक्षणाधीन है ताकि इन्हें मजबूत करने के लिए अपनाए गए उपायों की प्रभावकारिता का पता लगाया जा सके। ऊपर के दो तलों को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों के परिणामों से संतुष्ट हो जाने के बाद इन ऊपरी दो तलों को सितम्बर, 1993 में सौंप दिए जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में जेवर-जहांगीरपुर, स्थित चीनी मिल द्वारा चीनी का उत्पादन

4460. **चौधरी हरि सिंह** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जेवर-जहांगीरपुर, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिल द्वारा चीनी के उत्पादन हेतु अक्तूबर, तथा नवम्बर, 1993 के महीनों के दौरान किसानों से गन्ना खरीदे जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरान कितनी मात्रा में गन्ने के खरीदे जाने की संभावना है ; और

(ग) मिल द्वारा प्रतिदिन कितनी चीनी का उत्पादन किए जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जेवर-जहांगीरपुर स्थित चीनी मिल के आगामी चीनी मौसम 1993–94 के दौरान चीनी का उत्पादन करने की संभावना नहीं है और इस प्रकार अक्टूबर तथा नवम्बर, 1993 के महीनों के दौरान उक्त मिल द्वारा किसानों का गन्ना खरीदने की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Suggestion made by educare foundation

4461. SHRI SOM PAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news analysis by a noted writer in the Hindu (Delhi) of 4.7.93 on the wide spread incidence of Dyslexia in school going children;

(b) if so, what is Government's view in this matter;

(c) whether Government are aware of the suggestions made by the EDUCARE Foundation in this regard particularly exempting children from studying more than one language and allowing them extra time in exams;

(d) whether Government also know the measures taken by Karnataka Government in this regard;

(e) if so, what in the perception of the Central Government in these remedies; and

(f) whether Government would like to set up an experts panel to evaluate the incidence and suggest cares?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) Dyslexia is one of the conditions which constitute specific learning disability, including reading difficulty, in children. Dealing with learning difficulties, including reading difficulties, is already a part of general teacher training programmes. The Centrally Sponsored Scheme of Integrated Education for the Disabled Children (IEDC) also covers children with learning disabilities.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) The Central Government is not aware of the measures taken by the Karnataka Government.

(f) There is no proposal for setting up of an experts panel.

Poor promotion quota for K.V. teachers

4462. SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:

SHRI J. S. RAJU:

SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the teachers of Kendriya Vidyalayas are having promotion quota which is poorer than that of teachers of Union Territories; and

(b) if so, the details thereof and renetion of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) Kendriya Vidyalaya Sangathan has intimated that the ratio of Direct Recruitment quota and Departmental Promotion quota in the Recruitment Rules for teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan has been fixed on the basis of requirement of teachers in different subjects in the schools spread all over India. The Recruitment Rules of Kendriya Vdyalaya Sangathan, therefore, cannot be compared with those of the Union Territories.

Enrolment target in primary schools in Delhi

4463. SHRI KRISHAN KUMAR BIRLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the annual target, if any, for the enrolment at the primary school